

No.

Q:- SARFAESI एक्ट क्या है? इसके प्रमुख धारक क्या-क्या हैं? इसके अफलता की भारत में विवेचना करें।

SARFAESI Act

इसका पूरा नाम - Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act है। यह 2002 में आया। इसका निर्माण Debt Recovery Tribunal में ही रही थी एवं लंबित केस के कारण हुआ।

धारक

SARFAESI Act एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान Non-marketable assets को Marketable assets में बदल सकते हैं। अर्थात् ऋण वसूली हेतु व्यवसायिक व आवासीय संपत्तियों पर बली लगी जा सकती है। इसके प्रमुख धारक निम्नलिखित हैं -

→ इस अधिनियम में S का तात्पर्य Securitisation से है जिसका अर्थ ऋण वसूल करने हेतु बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान किसी Assets की मालिकी कर सकती है अथवा किसी अन्य कंपनी को सौंप सकती है।

→ Reconstruction of financial assets का तात्पर्य जी Asset reconstruction company देखती है कि Assets management के सभाव में खराब हुई है मरती इसका सन्दे में Management करती है एवं नहीं तो इसे बेच देती है।

→ Enforcement of financial assets का तात्पर्य है कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएँ ऋण बसूली के लिए न्यायालय में जाय बिना ही अपने Assets को बेच सकती हैं।

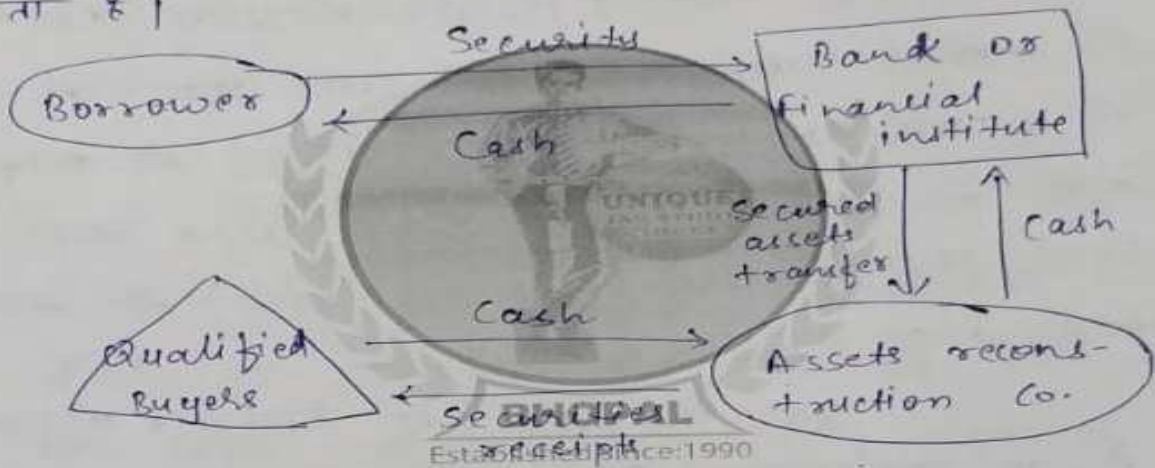
भारत में सफलता का विवेचना

BHOPAL

1993 से पूर्व बैंकों को ऋण बसूली के लिए न्यायालय में जाना पड़ता था। 1993 के बाद Debt Tribunal आया जिससे संबंधित मामले कम हुए परंतु फिर भी 93000 मामले संबंधित थे। इसके बाद जब 2002 में SARFAESI अधिनियम आया तब भारत में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को काफी आसानी से ऋण बसूली होने लगी।

इसके तहत कर्जकारता कर्ज देने तकत security जमा करते हैं एवं

अगर ऋण वसूली नहीं हो पाती तब इसे Asset re construction companies को बेज देते हैं। इन कंपनियों के Qualified Buyers से बिक होता है। जो इन Assets के पैसों कंपनी को देते हैं एवं कंपनी इसे बैंक को दे देती है जिससे बैंक का NPA कम होता है।



निष्कर्ष

SARFAESI अधिनियम आने में भारतीय मर्चण्यवस्था में काफी सुधार हुआ है क्योंकि बैंकों का NPA कम हुआ है। परंतु मरुत किन लंबित मामलों को जल्दी निपटारा करने हेतु इस अधिनियम में भी संशोधन होते रहते हैं। जैसे - 2016 के संशोधन जिसमें मध्यम एवं अन्त सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया।